ह्यूमन इंडिया

बजट से बदलेगी गुड़गांव की तस्वीर

रियल एस्टेट और शिक्षा जगत के प्रणेताओं को बजट से बड़ी उम्मीदें

ह्यूमन इंडिया/ब्यूरो

गुड़गांव। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरने वाला शहर गुडगाँव अपनी गगनचुम्बी इमारतों, उभरते उद्योग और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के लिए विख्यात है दुनियाभर की नामी-गिरामी कंपनियाँ गुडगाँव में अपनी मौजूदगी चाहती हैं इन कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनलों की वजह से दिन-प्रतिदिन यहाँ लक्जरी और अल्ट्रा-लक्जरी मकानों की मांग बढती जा रही है इसी वजह से गुडगाँव का रियल एस्टेट उद्योग फल-फूल रहा है वही शिक्षण संस्थानों के मामले में गुडगाँव पिछले 7-8 सालों में बहुत तेजी से उभरा है यहाँ एक से एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान खुल गए है जो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं।

परंपरागत उद्योगों और उनकी जरूरतों को हमेशा से महत्व दिया जाता रहा है और बजट में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है जबकि रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया जाता है रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र दोनों ही समाज के विकासस्तम्भ हैं, ऐसे में यह बहुत जरूरी है की इनकी मांगों को ध्यान में रखकर बजट में ऐसे प्रावधान लाये जायें जो इन क्षेत्रों की उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक सिद्ध हों बजट के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए इन क्षत्रों के कुछ प्रणेताओं ने अपने मत कुछ इस तरह रखे:

होमस्टेड के उपाध्यक्ष राजेश के गौरी ने कहा कि रियल एस्टेट बाजार यह आशा करती है कि एक लम्बे समय के मंदी के बाद बजट 2016 एक अच्छी उम्मीद लेकर आयगी आने वाले बजट के अंतर्गत, हम यह उम्मीद करते हैं कि बिल्डरों के द्वारा होने वाले देरी के मामले में निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए खरीदारों के लिए यह बेहद फायदेमंद रहेगी, यदि स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए भी मकान किराये में कटौती की सीमा बढ़ा दी जाए, चूँकि धारा 80 जीजी के तहत अभी मिलने वाली छूट मात्र 2000 रुपये है।

एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंस और अकाउंट के प्रेसिडेंट अतुल बंसल ने कहा कि पिछले एक दशक में धीमी वृद्धि के कारण, बहुत सी कमजोरीयों को दूर करने की जरूरत है जिसने विकास की गति को कम कर दिया है पिछले दशक के मध्य से आई हुई आर्थिक मंदी के बाद से रियल एस्टेट जगत ने उतार चढ़ाव झेला है हाँलाकि बीते कुछ समय से यह लग रहा है कि यह वापस अपने मार्ग पर लौट रहा है जिसके लिए सरकार की नीतियाँ और नए कानून सहयोगी है केंद्रीय बजट की प्रतीक्षा बेसब्री से हर कोई कर रहा है, कारण यह है कि घोषित नीतियों का प्रभाव अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक रहेगा इसलिए सकारात्मक या नकारात्मक, इसका असर सभी पर पड़ेगा चाहे वह किसी भी उद्योग से जुड़े हों तथ्य यह है कि इस साल रियल एस्टेट बाजार वापसी कर रहा है अत: रियल एस्टेट के लिए यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा महानगरों के परिधीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त आवंटन भी प्रदान करना चाहिए।

एटीडीसी के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ डार्लि कोशी ने कहा कि स्किलिंग इंडिया मिशन की सबसे बड़ी चुनौती नियोक्ताओं के हिसाब से छात्रों का उचित कौशल का मिलान करना है वर्तमान में भारत के अधिकतर राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं और काफ़ी मात्रा में ग्रामीण आबादी वाले रहे हैं इसके अंतर्गत यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आदि जैसे राज्य शामिल है नौकरियों विशेष रूप से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में ही उपलब्ध हैं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और ग्रामीण इलाकों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सफल रोजगारिक संबंधों के साथ कौशल मिशन को प्रोत्साहित करने की जरुरत है परिधान विनिर्माण न केवल 18 से 55 साल की उम्र के परिवारों के लिए उपयुक्त है बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्याप्त कौशल का प्रशिक्षण 45 से 60 दिनों में दिया जा सकता है यह महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त है जिसके जरिए वें निर्यात या घरेलू विनिर्माण इकाइयों में 6500 से 8500 प्रति माह रूपए की कमाई कर सकते हैं सरकार को परिधान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियों और राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाईयां की स्थापना करनी चाहिए।

द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल विक्रम मोहंती (सेवानिवृत्त) ने कहा कि उच्च शिक्षा का परिणाम युवाओं में रोजगार और राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है। हालांकि चिंता का विषय इस क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और उपयोगिता पर है। हम उम्मीद करते है कि सरकार निजी विश्वविद्यालयों में परियोजनाओं और अनुसंधानों के बेहतर प्रावधानों के लिए धन मुहैया कराए। निजी और स्वतंत्र विश्वविद्यालयों को भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास में समर्थन करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अधिक उदार बनते हुए, 10 साल के भुगतान की शर्तों के साथ सस्ती शिक्षा ऋण उपलब्ध करायी जाए।